

राष्ट्रीय · National

मदरसा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, शहरी भू-अभिलेख सुधार और RBI का NDS-OM विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के मदरसा निर्देश पर रोक लगाई; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शहरी भू-अभिलेख आधुनिकीकरण पर कार्यशाला शुरू की तथा RBI ने NDS-OM का दायरा बढ़ाया।

राष्ट्रीय · National

1. मदरसा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

- CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCPCR के पत्रों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई।
- अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संरक्षण का मुद्दा उठाया।
- राज्यों को गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर दंडात्मक कार्रवाई से रोका गया।

राष्ट्रीय · National

2. शहरी भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यशाला

- ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया।
- DILRMP के अनुभव के आधार पर शहरों में GIS मैपिंग और डिजिटलीकरण लागू होगा।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के संपत्ति कर प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय · National

3. RBI का NDS-OM प्लेटफॉर्म विस्तार

- सरकारी बॉन्ड ट्रेडिंग सिस्टम तक RRBs और NBFCs को पहुंच दी गई।
- द्वितीयक ऋण बाजार में तरलता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- पेंशन फंड और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी सीधे भाग ले सकेंगी।

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

DILRMP की शुरुआत	1 अप्रैल 2016 (शत-प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्रक योजना)
NDS-OM की स्थापना	अगस्त 2005 (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित)
NCPCR की स्थापना	मार्च 2007 (CPCR अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैधानिक निकाय)
RTE अधिनियम संशोधन	2012 संशोधन द्वारा मदरसों और धार्मिक संस्थानों को छूट
शहरी भू-अभिलेख कार्यशाला स्थल	डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC), नई दिल्ली

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

हाल ही में चर्चा में रहे 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग' (NDS-OM) प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है?

- A विदेशी मुद्रा का प्रत्यक्ष विनिमय
- B सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) का द्वितीयक बाजार व्यापार**
- C कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों का निपटान
- D कृषि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग

उत्तर / Answer: B — NDS-OM भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाला एक स्क्रीन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर-मैचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार व्यापार हेतु किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है?

A आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

B ग्रामीण विकास मंत्रालय

C इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

D पंचायती राज मंत्रालय

उत्तर / Answer: B — DILRMP ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) द्वारा शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण से क्रियान्वित की जाने वाली योजना है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends